आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 06.06.2025 समय : 1905

<><><><><><><><>

- भारत ने पिछले ग्यारह वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने नीट–पीजी दो हजार पच्चीस की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दी।
- ए बी वी पी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात कर कॉलेज के मुद्दों पर चर्चा की।
- सेल्यूलर जेल परिसर में नौ जून को मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी।

<><><><><><><><>

भारत ने पिछले ग्यारह वर्षों में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, और जलवायु कार्रवाई में एक वैश्विक नेता के रूप में भी उभरा है। देश ने वित्त वर्ष दो हजार चौबीस–पच्चीस में अक्षय ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड उनतीस दशमलव पांच दो गीगावाट जोड़ा, जिससे कुल क्षमता दो सौ बीस दशमलव एक शून्य गीगावाट हो गई। इसमें सौर और पवन ऊर्जा में तेजी से वृद्धि के साथ–साथ परमाणु क्षमता में पर्याप्त वृद्धि शामिल है। भारत अब अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में सातवें स्थान पर है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, विस्तारित जैव ऊर्जा कार्यक्रम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ते बदलाव जैसी पहल कम कार्बन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही हैं। भारत ने दो हजार तीस से नौ साल पहले ही गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का चालीस प्रतिशत प्राप्त करने के अपने COP21 लक्ष्य को हासिल कर लिया। ग्लासगो में COP26 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दो हजार सत्तर तक महत्वाकांक्षी पंचामृत लक्ष्यों की घोषणा की। उन्होंने पर्यावरण के लिए जीवनशैली, LiFE मिशन भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत व्यवहार के स्तर पर संधारणीय जीवन को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन का संस्थापक सदस्य और प्रमुख चालक है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारा ग्रह एक है, लेकिन हमारे प्रयास कई होने चाहिए।

<><><><><><><><>

भारत ने पर्यावरण संरक्षण और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विकास मॉडल अपनाया है, जो पर्यावरण संरक्षण को समावेशी विकास के साथ एकीकृत करता है। नदियों को पुनर्जीवित करने से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और हरित बुनियादी ढांचे के निर्माण तक, देश ने संरक्षण के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। नमामि गंगे मिशन दुनिया के सबसे बड़े नदी कायाकल्प कार्यक्रमों में से एक है। इसने जल की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैव विविधता को बढ़ाया है और गंगा के पुनरुद्धार में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत मिशन और गोबरधन योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बदल दिया है। "एक पेड़ माँ के नाम" जैसे अभियानों ने नागरिकों को पर्यावरणीय संरक्षण के लिए प्रेरित किया है, जो कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिक बहाली में योगदान दे रहे हैं। भारत ने वन्यजीव संरक्षण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन और विस्तारित प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहल आवास विकास और प्रजातियों की बहाली पर ध्यान केंद्रित करती हैं। भारत में बाघ की आबादी दुनिया की जंगली बाघ आबादी का पचहत्तर प्रतिशत से अधिक है। भारत में वर्तमान में इक्यानब्बे रामसर स्थल हैं, जो एशिया में सबसे अधिक है। तेरह भारतीय समुद्र तटों ने प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन अर्जित किया है, जबकि अमृत धरोहर और मिष्टी जैसी योजनाएं आर्द्रभूमि और मैंग्रोव के संरक्षण को आगे बढ़ा रही हैं, जो जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का हरित परिवर्तन एक नीतिगत पहल से कहीं अधिक है।

<><><><><><><>

सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट–पीजी दो हजार पच्चीस की परीक्षा तीन अगस्त को एक पाली में आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले यह परीक्षा पन्द्रह जून को निर्धारित थी, लेकिन बोर्ड ने परीक्षा आयोजित करने के लिए दो महीने से अधिक समय की मांग की थी। बोर्ड ने तीन जून को समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया कि उसे परीक्षा केंद्रों की संख्या दोगुनी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की जरूरत है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट–पीजी दो हजार पच्चीस की परीक्षा आयोजित करने के लिए बोर्ड को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा।

<><><><><><><>

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री विजयपुरम के दौरे पर आए पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में ए बी वी पी विभाग प्रमुख डॉ. कांडिमुत्थु, उपाध्यक्ष डॉ. राजीव तिवारी, संयुक्त सचिव एम. विनेश और ब्रुक्शाबाद स्थित पांडिचेरी विश्वविद्यालय में जेएनआरएम कॉलेज इकाई के कार्यकारी सदस्य गुरु प्रसाद शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों और पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध द्वीपों के कॉलेजों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ए बी वी पी ने कुलपति से पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में छात्रों के मुद्दों पर ध्यान देने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों को नियुक्त करने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने डीब्रेट के एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज को पुनः संबद्धता प्रदान करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने जे एन आर एम में कुछ विभागों में पीजी और शोध पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया। कुलपति ने प्रतिनिधिमंडल को हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।

<><><><><><><>

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य द्वीपसमूह के अपने आधिकारिक दौरे पर हैं। आयोग के सदस्य निरुपम चकमा और डॉ. आशा लकड़ा ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ वनवासी कल्याण आश्रम का दौरा किया। उन्होंने महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वनवासी कल्याण आश्रम के सम्मेलन कक्ष में एक संवाद सत्र आयोजित किया गया, जिसमें रांची समुदाय के सदस्यों ने अपने विचारों को साझा किया।

<><><><><><><>

द्वीपों के उप–राज्यपाल ने राजस्व विभाग की उच्च स्तरीय सेवाओं को सरल बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत अब नो–ड्यूस सर्टिफिकेट, नॉन–एंकमब्रेंस सर्टिफिकेट और मूल्यांकन प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है और इसे नौ जून से बंद कर दिया जाएगा। संपत्ति के मूल्य की गणना विभिन्न कारकों के आधार पर सर्किल रेट की अधिसूचना के अनुसार की जाएगी। पेट्रोलियम अधिनियम, उन्नीस सौ चौंतीस और लाइसेंसिंग पेट्रोलियम नियम, दो हजार दो के तहत अनिडको आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मांग के अनुसार नए पेट्रोल पंप खोलेगा। नए आदेश के अनुसार अब नाव की लाइसेंस के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और जहाजों का सर्वेक्षण अंतरद्वीपीय जहाजों के सर्वेक्षक द्वारा पूरी की जाएगी। राजस्व विभाग द्वारा वार्षिक सर्वेक्षण तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है।

<><><><><><><><>

आपदा की तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र का आंकलन करने के लिए नौ जून को सुबह ग्यारह बजे सेलुलर जेल परिसर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास कला और संस्कृति निदेशालय द्वारा आपदा प्रबंधन निदेशालय और प्रशासन के अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान परिसर और उसके आसपास मौजूद पर्यटकों और आगंतुकों से न घबराने की अपील की गई है। साथ ही अभ्यास में भाग लेने वाले अधिकारियों और स्वयंसेवकों को अपना पूरा सहयोग देने को कहा है।

<><><><><><><><>

जहाजरानी सेवा निदेशालय में मास्टर के पद के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार तेरह जून को शाम चार बजे मुख्य सचिव के कक्ष में आयोजित होगी। पात्र उम्मीदवारों से मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि और स्थान पर शाम साढ़े तीन बजे तक उपस्थित रहने को कहा गया है।

<><><><><><><><>